रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 फरवरी, 2005/6 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 002, 25 फरवरी, 2005

संख्या वि0 स0–विधायन–अनु0 बिल/1–15/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग

3779–राजपत्र/2005–25–2–2005–1,426. (3939) मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 25 फरवरी, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2005 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 के लिए 7,28,46,70,698 रुपये की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियों जिनका योग 7,28,46,70,698 रुपये (सात सौ अठाईस करोड़, छयालीस लाख, सतर हजार छः सौ अठानवें रुपये) हैं, संदत और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	कुल जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा	(राजस्व)	1,09,00,000	4,06,000	1,13,06,000
		(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000
2	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद्	(राजस्व)	80,00,000	4,65,000	84,65,000
		(पूंजी)	—	—	—
3	न्याय प्रशासन और निर्वाचन	(राजस्व)	5,67,34,000	10,13,000	5,77,47,000
		(पूंजी)	1,44,00,000	—	1,44,00,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	3,90,57,000	58,45,000	4,49,02,000
		(पूंजी)	—	—	—
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व)	7,82,43,000	75,000	7,83,18,000
		(पूंजी)	30,00,000	—	30,00,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	3,48,98,000	—	3,48,98,000
		(पूंजी)	—	—	—
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	5,19,11,967	—	5,19,11,967
		(पूंजी)	3,06,00,000	—	3,06,00,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	4,00,000	—	4,00,000
		(पूंजी)	4,85,00,000	—	4,85,00,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	2,35 96,000	—	2,35,96,000
		(पूंजी)	55,29,000	—	55,29,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
10	लोक निमार्ण - भवन	(राजस्व)	2,45,56,000	—	2,45,56,000
		(पूंजी)	68,64,000	—	68,64,000
11	कृषि	(राजस्व)	87,52,667	—	87,52,667
		(पूंजी)	—	—	—
12	उद्यान	(राजस्व)	6,18,73,000	—	6,18,73,000
		(पूंजी)	—	—	—
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	—	—	—
		(पूंजी)	8,000	53,25,284	53,33,284
14	पशुपालन, दुग्ध विकास	(राजस्व)	3,96,77,000	—	3,96,77,000
	एवं मत्स्य	(पूंजी)	15,00,000	—	15,00,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र	(राजस्व)	96,88,000	—	96,88,000
	उप - योजना	(पूंजी)	3,00,00,000	—	3,00,00,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	11,22,000	—	11,22,000
		(पूंजी)	—	—	—
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	2,50,00,000	—	2,50,00,000
		(पूंजी)	7,50,73,000	—	7,50,73,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	1,18,85,555	—	1,18,85,555
		(पूंजी)	2,00,000	—	2,00,000
19	सामाजिक न्याय और	(राजस्व)	1,000	—	1,000
	अधिकारिता	(पूंजी)	13,47,80,080	—	13,47,80,080
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	36,84,000	—	36,84,000
		(पूंजी)	—	—	—
21	सहकारिता	(राजस्व)	8,06,000	—	8,06,000
		(पूंजी)	9,44,82,000	—	9,44,82,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
22	खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व)	17,13,000	—	17,13,000
		(पूंजी)	—	—	—
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	3,08,30,000	—	3,08,30,000
		(पूंजी)	—	—	—
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	—	—	—
		(पूंजी)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	13,50,000	—	13,50,000
		(पूंजी)	—	77,00,000	77,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	36,90,000	—	36,90,000
		(पूंजी)	—	—	—
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास	(राजस्व)	1,15,38,04,000	—	1,15,38,04,000
	नगर विकास	(पूंजी)	47,63,92,000	5,84,446	47,69,76,446
29	वित्त	(राजस्व)	5,000	5,30,52,251	5,30,57,251
		(पूंजी)	—	4,48,73,04,548	4,48,73,04,548
30	विविध सामान्य सेवायें	(राजस्व)	2,00,59,900	—	2,00,59,900
		(पूंजी)	34,56,000	—	34,56,000
31	जन जातीय विकास	(राजस्व)	18,000	—	18,000
		(पूंजी)	8,08,61,000	—	8,08,61,000
		कुल जोड़	2,72,29,00,169	4,56,17,70,529	7,28,46,70,698
		(राजस्व)	1,70,22,55,089	6,08,56,251	1,76,31,11,340
		(पूंजी)	1,02,06,45,080	4,50,09,14,278	5,52,15,59,358

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
दिनांक 25 फरवरी, 2005.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन ए-सी. (2) 18/2004]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिये विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
दिनांक 25 फरवरी, 2005.

Bill No. 1 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2005.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2005. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 7,28,46,70,698 (Seven hundred twenty eight crore, forty six lakh and seventy thousand and six hundred ninety eight rupees only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2004-2005 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of a further sum of Rs. 7,28, 46,70,698 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2004-2005.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* Sections 2 and 3)

1	2		3		
De-mand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha	(Revenue)	1,09,00,000	4,06,000	1,13,06,000
		(Capital)	50,00,000	—	50,00,000
2	Governor and Council of Ministers.	(Revenue)	80,00,000	4,65,000	84,65,000
		(Capital)	—	—	—
3	Administration of Justice and Election.	(Revenue)	5,67,34,000	10,13,000	5,77,47,000
		(Capital)	1,44,00,000	—	1,44,00,000
4	General Administration	(Revenue)	3,90,57,000	58,45,000	4,49,02,000
		(Capital)	—	—	—
5	Land Revenue and District Administration.	(Revenue)	7,82,43,000	75,000	7,83,18,000
		(Capital)	30,00,000	—	30,00,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	3,48,98,000	—	3,48,98,000
		(Capital)	—	—	—
7	Police and Allied Organisation.	(Revenue)	5,19,11,967	—	5,19,11,967
		(Capital)	3,06,00,000	—	3,06,00,000
8	Education	(Revenue)	4,00,000	—	4,00,000
		(Capital)	4,85,00,000	—	4,85,00,000
9	Health and Family Welfare.	(Revenue)	2,35,96,000	—	2,35,96,000
		(Capital)	55,29,000	—	55,29,000
10	Public Works–Buildings	(Revenue)	2,45,56,000	—	2,45,56,000
		(Capital)	68,64,000	—	68,64,000

2		3		
		Rs.	Rs.	Rs.
Agriculture	(Revenue)	87,52,667	—	87,52,667
	(Capital)	—	—	—
Horticulture	(Revenue)	6,18,73,000	—	6,18,73,000
	(Capital)	—	—	—
Irrigation and Flood Control.	(Revenue)	—	—	—
	(Capital)	8,000	53,25,284	53,33,284
Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries.	(Revenue)	3,96,77,000	—	3,96,77,000
	(Capital)	15,00,000	—	15,00,000
Planning and Backward Area Sub-Plan	(Revenue)	96,88,000	—	96,88,000
	(Capital)	3,00,00,000	—	3,00,00,000
Forest and Wild Life	(Revenue)	11,22,000	—	11,22,000
	(Capital)	—	—	—
Roads and Bridges	(Revenue)	2,50,00,000	—	2,50,00,000
	(Capital)	7,50,73,000	—	7,50,73,000
Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	1,18,85,555	—	1,18,85,555
	(Capital)	2,00,000	—	2,00,000
Social Justice and Empowerment.	(Revenue)	1,000	—	1,000
	(Capital)	13,47,80,080	—	13,47,80,080
Rural Development	(Revenue)	36,84,000	—	36,84,000
	(Capital)	—	—	—
Co-operation	(Revenue)	8,06,000	—	8,06,000
	(Capital)	9,44,82,000	—	9,44,82,000
Food and Warehousing	(Revenue)	17,13,000	—	17,13,000
	(Capital)	—	—	—
Water and Power Development	(Revenue)	3,08,30,000	—	3,08,30,000
	(Capital)	—	—	—
Road and Water Transport	(Revenue)	—	—	—
	(Capital)	1,00,00,000	—	1,00,00,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	13,50,000	—	13,50,000
		(Capital)	—	77,00,000	77,00,000
27	Labour Employment and Training.	(Revenue)	36,90,000	—	36,90,000
		(Capital)	—	—	—
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban.	(Revenue)	1,15,38,04,000	—	1,15,38,04,000
		(Capital)	47,63,92,000	5,84,446	47,69,76,446
29	Finance	(Revenue)	5,000	5,30,52,251	5,30,57,251
		(Capital)	—	4,48,73,04,548	4,48,73,04,548
30	Miscellaneous General Services.	(Revenue)	2,00,59,900	—	2,00,59,900
		(Capital)	34,56,000	—	34,56,000
31	Tribal Development	(Revenue)	18,000	—	18,000
		(Capital)	8,08,61,000	—	8,08,61,000
		Grand Total	**2,72,29,00,169**	**4,56,17,70,529**	**7,28,46,70,698**
		(Revenue)	**1,70,22,55,089**	**6,08,56,251**	**1,76,31,11,340**
		(Capital)	**1,02,06,45,080**	**4,50,09,14,278**	**5,52,15,59,358**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2004-2005.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
Dated the 25th February, 2005.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C (2) 18/2004]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2005 recommends, under AArticle 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2005

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2005.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :
Dated the 25th February, 2005.